भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1504

23 सितम्बर, 2020 के लिए प्रश्न

'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना का कार्यान्वयन'

1504 श्री सतीश चंद्र दुबे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने 'अखिल भारतीय राशन कार्ड' योजना को लागू करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो 'अखिल भारतीय राशन कार्ड' योजना को लागू करने के लिए क्या योजना बनाई गई है; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों की प्रस्तावित भूमिका का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क): जी हां। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत कोई भी लाभार्थी देश में स्थित अपनी पसंद की किसी भी उचित दर दुकान पर उसी/मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अपनी पात्रता के खाद्यान्नों का उठान कर सकता है।

(ख): प्रारम्भ में अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा 4 राज्यों अर्थात निकटवर्ती राज्यों के दो क्लस्टरों में अगस्त, 2019 में शुरू की गई थी। अब तक 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एनएफएसए राशन कार्डों की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी राष्ट्रीय स्तर के एक क्लस्टर में सक्रिय कर दी है। इसके अलावा, दिनांक 31.03.2020 तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में यह सुविधा सक्रिय करने के उद्देश्य से यह विभाग शेष 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर यह मामला उठा रहा है। तथापि, शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसमें जोड़ने की प्रक्रिया उचित दर दुकानों पर इलेक्ट्रोनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों की स्थापना, लाभार्थियों के आधार/बायोमेट्रिक प्रमाणन को सक्रिय करने और अन्य तकनीकी पहलुओं के रूप में इसे कार्यान्वित करने की उनकी तैयारी पर निर्भर है।

(ग): चूंकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केन्द्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के संयुक्त दायित्व के तहत प्रचालित की जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण करने, सभी उचित दर दुकानों पर बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणन की सुविधा सक्रिय करने, उचित दर दुकानों के प्रचालनों के पर्यवेक्षण एवं निगरानी आदि की प्रचालनात्मक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार की होती है, अतः एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिका समाहित है।

*****